बिहार विधान-सभा वादवृत।

शुक्रवार, तिथि ३ अप्रील १९६४।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि ३ अप्रील १९६४ को पूर्वाह्न ११ बजे उपाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल के सभापतित्व में हुआ।

स्थगन प्रस्ताव।]

ADJOURNMENT MOTION.

उपाध्यक्ष--जो ऐडजोर्नमेंट मोशन्स आये थे वे नियमानुकल नहीं थे, इसलिये नामंजूर किये गये हैं। अब उसके संबंध में कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री कपिलदेव सिंह--नियम के अनुकूल नहीं हैं इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन जो सवाल आज राज्य में उठा हुआ है बिहार के विश्वविद्यालयों में क्या हालत हो रही है इस तरह की व्यवस्था से क्या छात्रों में अनुशासन रहेगा?

उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य की जो इस संबंध में भावना है उसे ध्यानाकर्षण सूचना देकर व्यक्त कर सकते हैं या प्रश्न के द्वारा पूछ सकते हैं। ऐडजोर्नमेंट मोशन की जो सूचनाएं मिली हैं उसकी प्रति सरकार के पास भेज दी गयी है जैसा कि नियम है।

अत्यधिक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण।

Calling attention on a matter of urgent public importance.

वेतन पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन।

REPORT OF THE PAY REVISION COMMITTEE.

*श्री रामानन्द तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि १३ फरवरी, १९६४ को मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि नहर का रेट कुछ बढ़ाया गया है और बेटरमेंट टैक्स ऐसी योजनाओं पर लगाया गया है जिनसे किसान फायदा उठा रहे हैं। इन सारी चीजों का जिक्र बजट में दिया हुआ है कि हम किस तरह से थोड़ा बहुत टैक्स और बढ़ाकर योजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं। नहर से करीब एक करोड़ रुपया आता है लेकिन किसानों के जिम्मे बहुत से रुपये गिर गये हैं। यह बात सही है कि किसानों की पैदावार भी आज अच्छी नहीं है लेकिन आज इन बड़ी-बड़ी योजनाओं को सफल बनाना चाहते हैं तो सबसे जरूरत इसकी भी है कि आपका सहयोग मिले और आपके माध्यम से किसानों के जिम्मे जो बकाये हैं उनकी वसूली हो।

अन्त में मैं आप सब लोगों की ओर से कह देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के मंत्री डा० के० एल० राव के प्रति हम बहुत आभारी हैं कि पिछले तीन-चार महीनों से वे बिहार की सिंचाई के मामले में, बिजली की दर को कम करने के मामले में काफी मदद कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के किसान जो गरीब हैं उनको सस्ते दर में बिजली मिले और इससे वे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। साथ-साथ सिंचाई के बारे में भी उनका ख्याल है और उनसे हमारी जो बातें होती हैं उसकी उन्हें चिन्ता है।

दूसरी बात यह है कि मैं अपने अफसरों को भी दाद देना चाहता हूं जो चौबीस घंटे सिंचाई का काम कर पूरे बिहार की सेवा कर रहे हैं। इसे यों कहा जाय कि शरीर के नसों में खून की उतनी ही जरूरत है जितना कि प्रान्त में सिंचाई के काम की। इसके बिना प्रान्त आगे बढ़ नहीं सकता। हमारे सिंचाई विभाग के जो अफसरान हैं, चाहे वह बिजली विभाग के हों, वे आपकी भावनाओं को समझते हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि जो टारजेट मुकर्रर किया गया है उसके पहले वे अपने काम को पूरा करेंगे और मुझे भरोसा है कि समय रहते वह टारजेट पूरा हो जायगा।

कटौती प्रस्ताव: राज्य-सरकार की सिंचाई नीति।

CUT MOTION : IRRIGATIONAL POLICY OF THE STATE GOVERNMENT.

श्री सूरज प्रसाद—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"the Provision of Rs. 1,72,23,500 for "Irrigation, etc. (Commercial)" be omitted. To discuss the irrigational policy of the State Government.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुए यह कहना चाहता हूं कि
सिंचाई मंत्री ने सिंचाई के सम्बन्ध में, उसके महत्व के सम्बन्ध में, जो बातें कही हैं उसके
सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती है। बिहार जैसे प्रान्त में जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत
कम है सिंचाई की सुविधा किसानों को मुहैया करना बड़ा ही आवश्यक है। बिहार में कृषि-
आय प्रति व्यक्ति ७० रुपया है तो पंजाब में १८२ रु०, बंगाल में १७६ रु०, उत्तर
प्रदेश में १०३ रु० और आसाम में २०८ रु० है, तो यह हमारी कृषि-आय है। बिहार
के अन्दर कृषि आय प्रति व्यक्ति बहुत कम है। दूसरी तरह हमारे प्रान्त में जो खाद्य-उत्पादन
है वह निश्चित नहीं है। वह कुछ घटता-बढ़ता रहता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त
तक हमने यह पाया है कि खाद्य उत्पादन १९५६-५७ में ५१.३५ लाख टन, १९५७-५८ में

३६.१७ लाख टन, १६५८-५६ में ६८ लाख टा और १६६०-६१ में ७० लाख टन हुआ है। इससे यह बात निश्चित होती है कि यहां की खेती मौनसून पर निर्भर करती है। हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरी बात हम यह देखते हैं कि कृषि उत्पादन के संबंध में जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि कृषि के उत्पादन के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् बहुत भूमिका अदा करती है और तीसरी योजना में इस बात का अन्दाजा किया गया है कि कृषि का उत्पादन जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिये उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है बल्कि इस संबंध में नकारात्मक विकास हुआ है। इस तरह हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि से २.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि इसलिये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है कि कृषि समूचे प्रान्त के लिये खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ कच्चा माल मुहैया करती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के जिम्मे जो इतना महत्वपूर्ण काम है उसका ख्याल करते हुए हमें बहुत निराशा पैदा होती है। सिंचाई मंत्री भाषण कर रहे थे तो हमें उम्मीद थी कि वे अपने भाषण में इस बात का जिक्र करेंगे कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में हमने सिंचाई का इतना काम किया है और इतना करना बाकी है। इसका एक एनालिटिकल पिक्चर हमारे सामने पेश करते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस तरह का भाषण तो हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं जब दीप बाबू इसके मंत्री थे और उनके भाषण में भी आमतौर से यह पाया जाता था। इसलिये उनके भाषण से कोई दिशा नहीं मिली, कोई प्रकाश नहीं मिला जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचते कि हमारे सामने क्या करना है और सिंचाई के संबंध में हमने क्या प्रगति की है और क्या होनेवाला है। जब हम अपने प्रान्त को दूसरे प्रान्तों के साथ तुलना करना चाहते हैं तो हमारा प्रान्त सिंचाई के मामले में बहुत पीछे है। आंध्र में जहां २५ प्रतिशत, आसाम में २० प्रतिशत, मद्रास में ३८ प्रतिशत, पंजाब में ४१ प्रतिशत, दिल्ली में ३६.५ प्रतिशत और बिहार में केवल २२.४ प्रतिशत सिंचाई में वृद्धि हुई है। और भी हम देखते हैं कि एश्योर्ड इरिगेशन की बिहार में २२ लाख एकड़ भूमि में व्यवस्था कर पाये हैं। तीसरी योजना में कहां तक प्रगति कर पायेंगे यह कहना कठिन है। मैं आपके सामने पूरे बिहार की सिंचाई की तस्वीर रखना चाहता हूं। दूसरी योजना में ३२ करोड़ का आवंटन हुआ था जिसमें २७ करोड़ खर्च हुआ था। तीसरी योजना में ७१ करोड़ का आवंटन है और खर्च ५४॥ करोड़ है। इस तरह हम देखते हैं कि योजनाओं के निर्माण में धीमापन है लेकिन खर्च बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि ऐश्योर्ड इरिगेशन में जितना विकास करना चाहते थे वह नहीं कर पाये हैं। १६४६-४७ में जो एरिया इरिगेट होता था वह ५३.२६ लाख एकड़ था। वह १६४७-४८ में ४८.७६ लाख हो गया और ५५-५६ में ४६ लाख एकड़ रहा और १६६० में वह आंकड़ा ५०.६५ लाख एकड़ हो गया। इस तरह सिंचाई की व्यवस्था दिनोंदिन घटती जा रही है। जहां हम १६४६-४७ में थे वहीं आज भी हैं। कुछ दिन पहले काउंसिल में राज्य मंत्री ने भाषण करते हुए बतलाया था कि ५६ लाख एकड़ में सिंचाई कर पाये हैं तो १६४६-४७ में हम ५३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करते थे। इस तरह सोलह वर्ष की आजादी के बाद और पहली, दूसरी और तीसरी योजनाकाल के अन्दर केवल चार लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था कर पाये हैं। इससे पता चलता है कि बिहार में खेती की कोई तरक्की नहीं हो रही है। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी हम जहां के तहां हैं।

सिंचाई के सम्बन्ध में जो अबतक हमारी प्रगति हुई है वह निराशाजनक है और इस प्रगति के आधार पर हम कैसे यह कहें कि तीसरी योजना के अंत होने पर हम दूसरे राज्यों के तुलना में उन्नति कर लेंगे। पहली योजना में चार लाख बासठ हजार एकड़ में सिंचाई की सुविधा जहां प्रदान करने की बात थी वहां हम सिर्फ दो लाख एकड़ में ही दे पाये हैं। इसी तरह से तीसरी योजना तक जहां ३६ लाख एकड़ में सिंचाई सुविधा पहुंचाने की बात

थी वहां अबतक १७ लाख एकड़ में कर पाये हैं। जबतक किसान सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तबतक इ से फायदा कैसे हो सकता है। बराज आप बनाते हैं लेकिन जबतक उससे पक्का चैनल नहीं बनाते हैं तबतक कैसे फायदा होगा। जहांतक चैनल बनाने का सवाल है उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। ट्यूबवेल गाड़ दिया जाता है लेकिन चैनल के अभाव में उससे सि । नहीं हो पाती है। १९५६-५७ में ट्यूबवेल के सम्बन्ध में बहुत हल्ला हुआ लेकिन पक्का चैनल के अभाव में उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिये चैनल का और खासकर पक्का चैनल का निर्माण होना बहुत जरूरी है। हमारे क्षेत्र में भी दो जगह चैनल के अभाव में सिंचाई नहीं हो रही है। ऐसे जगह पर ट्यूबवेल गाड़े गये हैं जिससे लोगों के खेत में पानी नहीं पहुंच पाता है। सरकार जो योजना लागू कर रही है उससे फायदा नहीं होने में यह कारण है कि उसमें बुनियादी दोष है। सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल करने के साथ-साथ उसके निर्माण का भी बहुत ही महत्व है। सिंचाई मंत्री ने भाषण करते हुए कहा था कि गंडक योजना बना रहे हैं, कोशी योजना बना रहे हैं, सोन यो ना । ना र हे हैं ले .क इस संबंध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पश्चिमी कोशी नहर पर जहां दो करोड़ रुपया अबतक तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर खर्च होना चाहिये था वहां अबतक सिर्फ ४९ लाख रुपया ही खर्च हो पाया है। इस रफ्तार से काम होगा तो कैसे हम लक्ष्य तक पहुंच पायेंगे ?

श्री महेश प्रसाद सिंह---माननीय सदस्य यह फीगर कहां से बोल रहे हैं ?

श्री सूरज प्रसाद---कहां से मिल गया इसको आप जानें। आपके ही जरिये से यह फीगर मिला है। मैं यह कह रहा था कि आप पच्छिमी नहर योजना पूरा करना चाहते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दो वर्ष पूर्व भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री दीप नारायण सिंह ने कहा था कि इस योजना को पूरा कर लगे लेकिन जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं उससे उम्मीद नहीं हो रही है कि आप इसको पूरा कर पायेंगे, इसको कह देना जरूरी है। कोशी में इतनी भयंकर बाढ़ आयी कि भूतपूर्व मंत्री महोदय को इसकी पूजा करनी पड़ी। पच्छिमी नहर के बन जाने से सिर्फ सिंचाई की ही सुविधा नहीं होगी, इसके बन जाने से बाढ़ का भी प्रकोप दूर हो जायगा लेकिन जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं उस प्रगति से यह उम्मीद नहीं होती है कि इसको तीसरी या चौथी योजना काल में पूरा कर सकेंगे।

अब मैं गंडक योजना के बारे में कहना चाहता हूं। गंडक योजना एक सस्ती योजना है जिससे २७ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। इस योजना पर तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में २० करोड़ रुपया खर्च होने वाला है लेकिन इस साल अभीतक १ करोड़ ८८ लाख रुपया खर्च होने वाला था लेकिन अभी तक ९८ लाख रुपया खर्च हुआ है। इस गति से पता नहीं चलता है कि आप इसको पूरा सकेंगे। आप डपोरशंख जैसी बातें करते हैं। बात बहुत करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है। आप वादा पर वादा करते चले जाते हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं होता है।

श्री रामानन्द सिंह---मेरा एक प्वायन्ट ऑफ आर्डर है। क्या डपोरशंख माननीय मंत्री के प्रति कह सकते हैं। यह शब्द अनपार्लियामेंटरी है।

श्री कर्पूरी ठाकुर---मंत्री के प्रति नहीं कहा गया है बल्कि यह शब्द सिंचाई विभाग के प्रति कहा गया है।

उपाध्यक्ष—मैं इपोरशंस को यहां असांसदीय नहीं मानता हूं।

श्री सूरज प्रसाद—गंडक योजना के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कितने सालों में यह योजना पूरी होगी, सरकार की गति से यह निश्चित मालूम नहीं पड़ता है। एक आश्चर्य की बात यह है कि वहां दो नाला बनकर तैयार है। यह तो वैसा ही हुआ कि बाप का पता नहीं लेकिन बेटा तैयार है। मैं यह पूछता हूं जब बराज नहीं बना है तो नाला से अभी क्या काम होगा? कई वर्षों से जो किसान अपनी-अपनी जमीन को कब्जे में रखते थे वे भी उस जमीन की पैदावार से महरुम हो रहे हैं और उनकी जमीन लेकर सरकार भी कोई काम नहीं कर रही है इसलिए मैं सरकार से पूछता हूं कि बराज के बनाने में क्यों देर हो रही है?

सोन बराज में रिहंड योजना से पानी मिलेगा इस आधार पर पहले काम शुरू हुआ था लेकिन बाद में बिहार और यू०पी० सरकार में कुछ मतभेद होने की वजह से यू०पी० की सरकार रिहंड से पानी नहीं देना चाहती है और अब कोयल नदी में बांध बांधकर उससे पानी लेने की योजना है। इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि बराज बन जाने के बाद भी वह सिंचाई का साधन नहीं बन सकेगा जबतक कि कोयल नदी में बांध न हो जाय। ऐसी स्थिति में कोयल नदी में कब बांध बंधनेवाला है इसे भी सरकार को निश्चित बता देना चाहिए।

श्री रामानन्द सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायन्ट ऑफ आर्डर है।

Hon'ble the State Minister is talking with the officials.

उपाध्यक्ष—मैंने नहीं देखा है। अगर माननीय राज्यमंत्री ने ऐसा किया हो तो उन्हें नहीं करना चाहिए।

श्री सूरज प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, किसानों से सरकार सिंचाई रेट बढ़ाकर लेना चाहती है, खुशहाली टैक्स लेना चाहती है। मेरे ख्याल से सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि एसेम्बली की अनुमति बिना रेट बढ़ाती जाय, उसके साथ ही जिन किसानों के साथ पांच, सात या नव वर्षों का सट्टा है उस अवधि के अन्दर उनपर सिंचाई रेट नहीं बढ़ाया जा सकता है। सरकार को मनमाने ढंग से रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। सरकार का कहना है कि वह सिंचाई रेट इसलिए बढ़ाना चाहती है कि कौस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया है और सरकार को पैसे की जरूरत है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई योजना के निर्माण पर जो खर्च होता है उसके आधार पर सिंचाई का रेट बढ़ाना उचित नहीं होगा। चूंकि सिंचाई योजनायें मल्टी-परपस स्कीम्स हैं जिनसे बाढ़-नियंत्रण, बिजली उत्पादन और सिंचाई का काम होता है। अगर किसानों से योजना के ऊपर हुए खर्च के आधार पर सिंचाई रेट लिया जायगा तो वह उनकी क्षमता के बाहर की बात होगी। चूंकि वह बहुमुखी योजना है इसलिए उसके कौस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर सिंचाई रेट नहीं लिया जाना चाहिए। पांच-सात वर्ष पहले अशोक मेहता रिपोर्ट में यह सिफारिश हुई है कि सिंचाई रेट निर्धारण कास्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि किसानों के देने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। करीब १२ वर्षों के दरम्यान दो बार सिंचाई रेट बढ़ाया जा चुका है। आज किसानों की माली हालत ऐसी है कि वे लगान को भी समय पर देने में असमर्थ हैं

तब लेवी जो लगा है उसको वे कैसे दे सकते हैं ? इसलिए जो लगान में इजाफा हुआ है उसको वापस लेना चाहिए।

दूसरी बात में सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं। अभी हमारे यहां पर सिंचाई के लिए सात साला और एक साला जमीन का लीज होता है। कहीं-कहीं पर तो ९ साल या १० साल का भी लीज होता है। लेकिन एक साल का लीज होने से समय पर किसानों को पानी नहीं मिलता है। सिंचाई विभाग से किसान बराबर सात साला लीज करने के लिए कहते हैं लेकिन इस विभाग से यह कहा जाता है कि ६० प्रतिशत रेट की वसूली नहीं होती है और इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। रेट की वसूली का सर्टिफिकेट के लिए किसान तहसीलदार के पास जाते हैं तो वे उनसे घूस मांगते हैं और घूस देने पर उनको सर्टिफिकेट देते हैं। घूस नहीं देने से किसानों का सात साला लीज नहीं हो रहा है और इस तरह से किसानों से दो तरह का रेट वसूल किया जाता है और इस तरह से उनको लूटा जाता है। वहां पर एक रब्बी की फसल और दूसरी खरीफ की फसल होती है और इसलिए मैं यह चाहता हूं कि सात साला लीज करके एक साला लीज की परम्परा को खत्म करना चाहिए। इसी ओर सरकार का जल्द-से-जल्द कदम उठना चाहिए। अभी एक साला की नीति अपनाकर यह सरकार साइलौक की नीति किसानों के प्रति बरतती है और एक-एक बूंद खून उनसे वसूल करती है। ऐसा होने से न जमीन की सिंचाई का ही इंतजाम होता है और न जमीन की पैदावार ही बढ़ती है। इसलिए सरकार को इस नीति को बदलना चाहिए।

अब मैं कुछ बाढ़ की समस्या पर बोलना चाहता हूं। कोशी नदी की बांध की यहां पर बड़ी चर्चा होती है और उसके सम्बन्ध में तरह-तरह की बात सुनने में आती है। कुछ एक्सपर्ट लोगों का यह कहना है कि बांध के पीछे मिट्टी जमा हो रही है, ८० करोड़ फीट में मिट्टी भर गयी है। बराहक्षेत्र के नजदीक यह चीज हो रही है और धीरे-धीरे जब मिट्टी भर जायेगी तब बांध मिट्टी से ही भर जायेगी और वह बेकार हो जायेगी। इसको लेकर बाढ़ का प्रकोप हो सकता है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसके पीछे बुनियादी कारण क्या है और इससे क्या खतरा हमलोगों को है, इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और इसके रोकथाम का उपाय भी होना चाहिए।

इसके बाद सरकार का ध्यान गंगा नदी की ओर ले जाना चाहता हूं। इसके किनारे बांध का कोई खास इंतजाम नहीं है और इसके चलते लाखों एकड़ जमीन हर साल गंगाजी काटकर बहा ले जाती है और लाखों मन गल्ला भी बर्बाद हो जाता है। इसको रोकने का भी सरकार को कुछ इंतजाम करना चाहिए। सिंचाई विभाग में दूसरे विभाग से ज्यादा रुपया खर्च होता है और इस साल भी २७ या २८ करोड़ रुपया खर्च होनेवाला है। लेकिन इसका रुपया सही ढंग से खर्च नहीं होता है। किसी कंट्राक्टर को तो बिना टेंडर मांगे और दिये ही कंट्राक्टरी मिल जाती है। इस सम्बन्ध में कौंसिल में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उपस्थित किया गया था।

आज से कुछ दिन पहले विधान-परिषद् में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर माननीय मंत्री ने जवाब दिया था कि बिना टेंडर इनवाइट किये कंट्रैक्ट नहीं देते हैं। मगर बिना टेंडर इनवाइट किये कन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। इसके साथ-ही-साथ मंत्री महोदय ठेकेदारों के साथ निकटतम सम्बन्ध रखते हैं। ५ लाख का काम होता है तो उसके लिए १० लाख का बिल बनता है और पेमेन्ट भी हो जाता है। कोई भी इंजीनियर इन ठेकेदारों के काम को चेक नहीं कर सकता है, क्योंकि मंत्री महोदय नाखुश हो जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस विभाग में २८ करोड़ रुपया खर्च होता है तो उसके लिए सही नीति निर्धारित होनी चाहिए, सही ढंग से रुपया का खर्च होना चाहिए तथा सिंचाई व्यवस्था का सही ढंग से निर्माण होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं दो-एक सुझाव देकर बैठ जाना चाहता हूं। दूसरे प्रांत में सिंचाई के विकास के सम्बन्ध में छानबीन करने के लिए इरीगेशन डेवेलपमेंट कमिटी है, लेकिन बिहार में नहीं है। यह कमिटी छानबीन कर सकती है कि कहां खर्च करना उचित होगा और कहां अनुचित होगा। इसलिए सरकार से अर्ज करना है कि यहां भी इरीगेशन डेवेलपमेंट कमिटी का निर्माण किया जाय। दूसरा सुझाव में यह पेश करना चाहता हूं कि पटवन की व्यवस्था ठीक से नहीं होने के कारण रबी तथा खरीफ का पटवन ठीक से नहीं होता है। शाहाबाद जिले में रेलवे लाइन के समीप ही नहर खत्म हो जाता है। इसके बाद पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी बहकर गंगा में चला जाता है मगर उसको उपयोग में नहीं लाया जाता है। इस पानी को रब्बी के पटवन में लाया जा सकता है। इन जगहों में पानी का इंतजाम ठीक से हो जाय तो किसान ज्यादा उत्पादन करेगा जिससे किसान को तथा सरकार को फायदा है। मेरा सुझाव है कि इन जगहों में नया चैनल बना दिया जाय जिससे पानी की अच्छी व्यवस्था हो सके। बिजली के बारे में इन्होंने कहा कि हमने बिजली की दर में कमी कर दी और आपने तालियां बजायीं। ठीक है ताली में भी बजाने के लिए तैयार हूं यदि ताली बजाने का काम हो।

उपाध्यक्ष—आप बैठ जायें, समय हो गया है।

श्री सूरज प्रसाद—मैं एक मिनट में खत्म करता हूं। आपने कहा कि केन्द्रीय सरकार व्यवस्था कर रही है कि ९ नये पैसे की दर से बिजली मिले। आपको मालूम है कि पंजाब में, मद्रास में तथा दूसरे प्रदेशों में बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ९ नये पैसे की दर से बिजली दी जा रही है।

समय के अभाव से मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जनक सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो मांग सदन के समक्ष पेश की है उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही चंद शब्द सदन में इस संबंध में रखना चाहता हूं। महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी जिस समय अपनी मांग सदन में पेश कर रहे थे, मैं उनका भाषण ध्यानपूर्वक सुन रहा था। इसलिए ध्यानपूर्वक सुन रहा था कि माननीय मंत्री अपने भाषण में बागमती के सम्बन्ध में कुछ अवश्य कहेंगे। लेकिन मुझे दुःख हुआ कि बागमती के सम्बन्ध में एक शब्द भी माननीय मंत्री के भाषण में नहीं आया। चार-छः महीने पहले मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में एक बागमती कांफ्रेंस हुआ था जिसमें माननीय सिंचाई मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री तथा केन्द्रीय सिंचाई मंत्री श्री राव भी पधारे। उस कांफ्रेंस में जिस तरह से बातें हुई थीं उससे कुछ आशा की झलक मिली थी। लोगों को आशा बंधी कि बागमती के सम्बन्ध में कुछ अवश्य होगा। लेकिन मंत्री महोदय के भाषण से निराशा होती है। सरकार की उपेक्षा नीति बागमती के सम्बन्ध में सर्वदा निन्दनीय है। सचमुच बागमती को यदि योजना का रूप नहीं दिया गया तो राज्य को बड़ी हानि होनेवाली है। माननीय मंत्री ने बताया कि कोशी योजना बन गई। सोन और गंडक योजना को कार्यान्वित करने जा रहे हैं। लेकिन मैं बड़े अदब से पूछता हूं कि बागमती क्षेत्र के रहनेवाले लोगों ने क्या कसूर किया? क्यों उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है? बागमती का पानी और पंक ऐसा है कि जिस जमीन पर इसे पहुंचाया जायेगा उसपर खाद देने की जरूरत नहीं होगी। आप खाद तैयार करने तथा वितरण करने पर कितना खर्च करते हैं? अगर उसी अनुपात से आप बागमती पर खर्च करें तो मुफ्त में आपको खाद और सिंचाई दोनों अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे लेकिन आपके विशेषज्ञों का ध्यान इस ओर नहीं जाता।

मालूम होता है कि अब इंजीनियरिंग विभाग की सारी इंजीनियरी खत्म हो रही है। माननीय मंत्री ने कहा कि उत्तर बिहार में पानी अधिक उपलब्ध है। मगर आप जानते हैं कि उत्तर बिहार बाढ़ और सुखार दोनों से परेशान होता रहता है। इसलिए आग्रह है कि इंजीनियर अपनी कला का प्रदर्शन करें और उत्तर बिहार में उपलब्ध पानी का सही इस्तेमाल करें जिससे उत्तर बिहार बाढ़ और सूखा से बचे। खासकर मैं बागमती नदी को पालतू बनाने के लिए आग्रह करता हूं जिससे उस क्षेत्र के लोग लाभान्वित हों। कहा जाता है कि बागमती का सम्बन्ध नेपाल से है और जबतक नेपाल के साथ व्यवस्था नहीं होती है तबतक इसकी व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। बड़ी योजना के सम्बन्ध में मैं इस बात के औचित्य को मान सकता हूं मगर बागमती का जल सिंचाई के लिए मिले, लोगों के खेत पटें तथा पैदावार बढ़े, इसके लिए व्यवस्था हो सकती है। पैदावार बढ़ने से बिहार लाभान्वित होता है और बिहार लाभान्वित होता है तो देश लाभान्वित एवं धन-धान्य से पूर्ण होता है।

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जबतक आप इसके लिए कोई योजना बनाने नहीं जा रहे हैं तब तक बिजली जो आपके पास है, मेरा ख्याल है कि इसके द्वारा आप बागमती नदी का पानी किनारे के रहनेवाले लोगों को दे सकते हैं। सुनने में आता है कि दूसरे देशों में प्रति एकड़ ३०-४० मन पैदावार होती है। आज अगर आप बागमती का पानी खेतों में पहुंचा सकें तो ये खेत भी बिना ३०-४० मन प्रति बीघा पैदावार दिये नहीं रह सकते। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि जबतक आप कोई योजना के रूप में कुछ करने नहीं जा रहे हैं तबतक बिजली के माध्यम से आप लिफ्ट इरीगेशन का काम शीघ्र शुरू करें जिससे बागमती के किनारे रहनेवाले लोगों को लाभ हो और वे राज्य की पैदावार बढ़ाने में समर्थ हों।

एक दूसरी बात आर्टिजन टयूबवेल्स के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे टयूब-वेल्स बनाये गये हैं जो हमेशा बिना बिजली के पानी देते रहते हैं। आपको जानकारी होगी कि इसी सदन के सदस्य श्री शकूर अहमद साहब ने ऐसे टयूबवेल्स बनवाये हैं; प्रांतीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञों ने इसकी जांच की और उपयोगी पाया। मेरा ख्याल है कि अगर छानबीन हो तो ऐसे बहुत-से टयूबवेल्स उपलब्ध हो सकते हैं जिनसे बिना बिजली के सिंचाई हो सकती है।

तीसरी बात यह है कि माननीय मंत्री ने बतलाया है कि मैंने नदियों में बांध बंधवाया है जिससे लाभ हो रहा है। तो मैं बांध के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि बांध बनवाने के सिलसिले में ऐसा होता है कि जिनकी जमीन ली जाती है या जिनकी फसल इसमें कट जाती है वे बेचारे मुआवजा के इंतजार में बैठे रहते हैं और आप ऐसी मुसीबत की घड़ी में जब सरकार बन्दूक के कुन्दा के जोर पर उनसे ऋण तथा मालगुजारी का रुपया वसूल करती है और वे आपका दरवाजा खटखटाते हैं तौभी कोई सुनवाई आपके यहां नहीं होती। एक नहीं सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इस सिलसिले में आप कोई तेज और ठोस कदम उठायें जिससे मुआवजा का रुपया उन्हें जल्द-से-जल्द मिल जाये। मिसाल के लिए मैं यह बतलाऊं कि मुजफ्फरपुर में अखाड़ा घाट से मीनापुर तक जानेवाली बांध के सिलसिले में अभीतक ५० प्रतिशत लोगों के रुपये बाकी पड़े हुए हैं। माननीय मंत्री शीघ्र ध्यान देंगे यही आग्रह है। टयूबवेल्स पर रुपये खर्च हुए हैं लेकिन अगर उनकी जांच-पड़ताल हो तब यह मालूम होगा कि कितनी कैपेसिटी के वे हैं और कितनी जमीन की सिंचाई वे कर सकते हैं तथा उतनी सिंचाई हो पा रही है या नहीं? मेरा कहना यही है कि सिंचाई से आप पैदावार ज्यादा बढ़ायें। सिंचाई और फसल का बड़ा घना सम्बन्ध है। फसल बढ़ाने में हमारे टयूबवेल्स किस हद तक कामयाब हो रहे हैं यह देखने की आवश्यकता है। जांच-

पड़ताल से यह भी पता चलता है कि ट्यूबवेल्स ही उपयोगी हैं। लेकिन उनके व्यवधान कुछ ऐसे हैं जिससे वे लाभकर सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। पानी लेनेवाले को एग्रीमेंट करना होगा। एग्रीमेंट करने पर पानी लें, मान लें—लेकिन उन्हें एग्रीमेंट के अनुसार पेमेन्ट करना होगा। एक तो रेट बढ़ा हुआ, दूसरे किसानों को मौनसून पर निर्भर रहने की आदत और तीसरी बात एग्रीमेंट के बाद आवश्यक पेमेन्ट—यह कुछ ऐसा नियम है जिससे किसान इस ओर आकर्षित नहीं होते। इसलिए इस नियम में तथा रेट में सुधार की आवश्यकता है। जब किसान सिंचाई के अभ्यस्त होंगे तो पूरा रेट देंगे और एग्रीमेंट भी खुशी से करावेंगे।

इसी संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्यूबवेल को स्थानीय पंचायत के हाथ में सरकार दे। स्थानीय पंचायत के द्वारा इसका प्रचार और प्रसार अधिक हो सकता है और इससे लोग लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा मौका आता है कि किसान पानी लेना चाहते हैं और उन्हें समय पर नहीं मिलता। इसलिए मेरा कहना है कि स्थानीय पंचायत के हाथ में इसे दे दिया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उत्तर बिहार की तरफ, खास करके बागमती के बेल्ट की तरफ सरकार ध्यान दे।

*श्री रउफुल आजम—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सूरज प्रसाद के कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और इरिगेशन के मुतल्लिक में चन्द बातें अर्ज करना चाहता हूं। इरिगेशन मिनिस्टर का भाषण जो मैंने सुना उससे मालूम हुआ कि इन्द्र देवता की तरफ से बहुत जबर्दस्त बारिश हो रही है और हमलोग सदन में बहुत खुश हैं और बाहर में काफी पैदा हो रही है। बहुत-से अलफाज इसके सम्बन्ध में इस्तेमाल किये गये जिनसे मालूम हुआ कि इसके लिए बहुत-कुछ काम हो रहे हैं। मगर हम इरिगेशनल पौलिसी को कसौटी पर कसते हैं, जांच करते हैं तो पता चलता है कि यह फेल्योर रहा है और जितने की मांग हुई है वह सब वेस्टफुल एक्सपेन्डिचर है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि काश्तकार की तरफ धोखे की आड़ में पर्दा रखकर बटेर का शिकार किया गया है। मुझे यह कहना है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को बहुत हिस्सों में बांट दिया गया है। यह भी आपने कहने की कोशिश की कि महकमा इतना ज्यादा है और आफिसर इतने ज्यादा हैं, जैसा कि आपने उनसे दावा भी करा लिया है कि काम करने में दिक्कत नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जिस प्राविन्स की आबादी एग्रिकल्चर पर निर्भर करे उसके लिए क्या कारण है कि आपने जो डिमांड रखा है उसके प्रोपोरशन में उत्पादन नहीं होता है। दी रिजल्ट इज नौट इन प्रोपोरशन टू दी डिमांड। देयर इज नो ऐप्रिसिएबुल रिजल्ट। मैं देखता हूं कि इसके अन्दर बहुत-सी खामियां हैं।

आपने कितने चीफ इंजीनियर बहाल किये, कितने सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर बहाल किये, कितने एक्जीक्युटिव इंजीनियर बहाल किये और कितने असिस्टेंट इंजीनियर बहाल किये उसका फीगर में आपके सामने देना चाहता हूं।

इरिगेशन में आपके दो चीफ इंजीनियर हैं, १० सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, ४१ एक्जीक्युटिव इंजीनियर और १५६ असिस्टेंट इंजीनियर हैं यानी कुल २०९ अफसर हैं।

एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आपकी मदद के लिए है उसमें एक चीफ इंजीनियर, तीन सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, ११ एक्जीक्युटिव इंजीनियर और ३३ असिस्टेंट इंजीनियर हैं यानी कुल ४८ अफसर हैं।

कोशी में एक चीफ इंजीनियर, चार सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, २० एक्जीक्युटिव इंजीनियर और ७८ असिस्टेंट इंजीनियर हैं यानी कुल १२३ अफसर हैं।

गंडक में एक चीफ इंजीनियर, चार सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, १४ एक्जीक्युटिव इंजीनियर और ७३ असिस्टेंट इंजीनियर हैं यानी कुल ९२ अफसर हैं।

युनिफायड माइनर इरीगेशन में एक चीफ इंजीनियर, चार सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, १८ एक्जीक्युटिव इंजीनियर, १२१ असिस्टेंट इंजीनियर हैं यानी कुल १४४ अफसर हैं।

सब मिलाकर छः चीफ इंजीनियर, २५ सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, १०४ एक्जीक्युटिव इंजीनियर और ४८१ असिस्टेंट इंजीनियर हैं। ये आपके अफसर हैं। उनके ऊपर आपके जो एखराजात हैं उसको देखना होगा कि यह प्रोपोर्शन टु दी वर्क एंड रिजल्ट है या नहीं। मेरा किसी पर आरोप लगाने की मंशा नहीं है। गंडक प्रोजेक्ट का एक नमूना मैं आपके सामने पेश करता हूं। गंडक प्रोजेक्ट चल रहा है नौर्थ बिहार में, उसका कोई भी पोर्शन साउथ में नहीं है लेकिन उसका चीफ इंजीनियर पटने सेक्रेटेरियट के अन्दर है। वह यहां बैठकर क्या जाने कि जनता को क्या परेशानी है। एक अम्वा मौजा है मझौलिया थाने में। एक ग्रेभयार्ड होकर एलाइनमेंट बनाया गया है जिसके लिए वहां के लोगों ने चीफ इंजीनियर को, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर को, एक्जीक्युटिव इंजीनियर को लिखा लेकिन उसका जो रिजल्ट हुआ उसको मैं पढ़ देता हूं। गूहा साहब ने श्री अब्दुल हुसैन, सेक्रेटरी जमायतुल अम्वा, बेतिया के पास इस प्रकार का खत लिखा:

"On enquiry it has been found that survey plot nos. 2487 and 2488 are not recorded as graveyard in the survey map. In the circumstances, there appears to be no necessity of considering any change in the alignment of Tirhut canal."

जहां पर मसजिद है, मन्दिर है, ग्रेभयार्ड है उसके होकर अगर कैनाल का एलाइनमेंट हो और कहा जाय तो बिना बड़े अफसर की इन्क्वायरी के कह दिया जाता है कि यह सर्वे प्लौट में नहीं है।

बी०डी०ओ० की रिपोर्ट पर कह दिया जाता है कि एलाइनमेंट को बदलने की जरूरत नहीं है। आप उनको डिट्टो करते हैं, जनता कम्प्लेन करती है उसपर आप गौर नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि जनता की तकलीफ को आप नहीं हटा सकते हैं, कहीं बैड इनसिडेन्ट हो जाय, कहीं कोई हादशा हो जाय तो किसकी जिम्मेदारी होगी?

अब मैं बताता हूं कि सिर्फ कोशी डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर के ऊपर कितना खर्च है। उनके पे पर खर्च है १६,८०० रु०, टी०ए० में है ९ हजार और फिर कन्टीन्जेन्सी में है २० हजार सालाना। इस टी०ए० के रुपये से पटने से भैसालोटन आदि जगहों में उन्हें जाना है। आप इतना रुपया उनके ऊपर खर्च करते हैं। आप इतना खर्च करते हैं तो यह भी मालूम होना चाहिए कि कितनी प्रगति हुई है उसमें। आपने वायदा किया कि फर्स्ट, सेकेन्ड और थर्ड प्लैन में पूरा कर देंगे लेकिन मैं चश्मदीद गवाह हूं वहां कोई प्रोग्रेस नहीं है, वहां लेथारजी से काम चल रहा है, आपका जो टारजेट है अंजाम नहीं पा सका है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि गंडक ब्रिज में अफसरों को रखना है तो उनको साइट पर ही रखें, पटने में रहना कम करें। बेतिया से दक्षिण और उत्तर इसे ले जाना है, इसकी तीन शाखायें जा रही हैं।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मनियारी के अन्दर त्रिवेणी कैनाल है जिसमें तीन माईल डाउन डिस्ट्रीब्युटरी है। उसमें स्लूईश गेट बनाने के लिए पास किया गया, कितना प्रयास किया गया, इसके लिए हमने भी लिखा, जवाब आया कि एस्टीमेट बन

रहा है, उसके बाद मालूम हुआ कि एस्टीमेट सेक्रेटेरियट चला गया और जब यहां पता लगाया तो मालूम हुआ कि फाइल ही भूल गयी, काम ज्यों-का-त्यों पड़ा है। एस्टीमेट पास होकर सेक्रेटेरियट में आवे और यहां फाइल भूल जाय, कागज गायब हो जाय तो फिर क्या जरूरत है ऐसे अफसरान के रहने की, उनपर जनता के पैसों को बर्बाद न करें।

आपने डिवीजन किया, यूनिफायड इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, आदि, आदि। जिस वक्त पटेल साहेब इसके इनचार्ज थे मैंने क्वेश्चन किया था कि चम्पारण में इंजीनियर हैं या नहीं, एक-ब-एक मालूम हुआ कि वहां तो अफसरान हैं। उनके ऊपर इतने खर्च हुए लेकिन जितनी स्कीमें गयीं कोई कारगर नहीं हुई। आपने कर दिया कि ब्लौक के मारफत काम होगा। आपने यह भी किया कि दस हजार से ऊपर माईनर इरिगेशन करेगा, इतना होने से यूनिफायड इरिगेशन करेगा, नतीजा हुआ जितने महकमे लादते गये सब कहते हैं यह हमारे जिम्मे नहीं है।

फ्लड कंट्रोल के बारे में.........

श्री वीरचन्द पटेल---माइनर इरिगेशन का क्या हुआ? हम माईनर इरिगेशन ही रखना चाहते थे लेकिन महेश बाबू मेजर बनाने जा रहे हैं।

श्री रउफुल आजम---जब महेश बाबू इसके मंत्री हुए तो हमलोगों ने सोचा वे पुराने तजुर्बेकार मंत्री हैं, लोगों को उनसे बहुत तमन्नायें थीं....

सिंचाई विभाग जब आपके हाथ में आया तो लोगों को बहुत बड़ी तमन्ना थी कि आपसे बड़ी मदद मिलेगी लेकिन जब आपके कामों पर गौर किया गया तो सभी तमन्नाएं खत्म हो गयीं। हमने देखा है कि आपके हाथों में भी आकर सिंचाई विभाग में कोई तरक्की नहीं हुई। आपने दक्षिण बिहार के लोगों को आश्वासन दिया था कि हम नलकूप बैठायेंगे लेकिन क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि आपने इस दिशा में कौन-सा कदम उठाया है। मैंने भी आपसे अर्ज किया था कि दक्षिण बिहार में फ्लड के कारण कितने क्षेत्र बर्बाद हो गये हैं किन्तु आपने अभीतक ड्रेनेज वगैरह का कोई इंतजाम नहीं किया है। आपका जो वाटर टैक्स है उससे भी लोग परेशान नजर आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चम्पारण में वाटरवेज और ड्रेनेज का क्या काम हुआ है और इस मामले में आपके एस०डी०ओ० और इंजीनियर ने क्या किया है। वे लोग सिर्फ भत्ता उठाने के फेरे में लगे रहते हैं लेकिन जनता की तकलीफों की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। फिर भी आपकी तरफ से उन्हें थैंक्स मिलता है। मिनिस्टर साहब का साया तो उनलोगों पर हमेशा रहता है तो यह थैंक्स किस बात की। अगर इस अपोजीशन की तरफ से उन्हें थैंक्स मिलता तो यह सही माने में समझा जाता कि उनका काम अच्छा हो रहा है। अगस्त से सितम्बर तक आप किसानों को पानी देते हैं लेकिन उनपर १५ रु० प्रति बीघा टैक्स वसूल करते हैं, जो बहुत ही कड़ा है। आपका पानी वेस्टेज हो जाता है लेकिन आप जनता को कम रेट पर नहीं देना चाहते हैं। एक फसल में १० रु० प्रति बीघा टैक्स के रूप में लेते हैं। इस तरह से दोनों फसल लगाकर २५ रु० प्रति बीघा टैक्स आप किसानों से लेते हैं। इसलिए मेरा अर्ज है कि आप पहले जिस तरह से टैक्स लेते हैं उसी तरह से फिर से १० रु० और ७॥ रु० टैक्स लें। दूसरी बात आपसे मेरा अर्ज यह है कि लीज के मुताबिक किसानों को सालोंभर पानी मिलना चाहिए जो नहीं मिलता है, इसमें सुधार लाया जाय। आज आप जनता की गाढ़ी कमाई को अफसरों पर बेहिसाब खर्च करते चले जा रहे हैं, पर फायदा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है।

एक बात का और मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि १९६४ के अक्तूबर में आई०एस०ई० का कैडर होने जा रहा है और जो परमानेन्ट एक्जीक्युटिव इंजीनियर होंगे, वही आई०एस० ई० कैडर में ले लिये जायेंगे और आपके यहां के इंजीनियर छूट जायेंगे क्योंकि आपने उन्हें परमानेन्ट एक्जीक्युटिव इंजीनियर नहीं बनाया है। इस तरह से बाहर के लोग आई०एस०ई० कैडर में चले आयेंगे। अब मैं बैठ जाता हूं।

(श्री शीतल प्रसाद भगत बोलने के लिए खड़े हुए। सदन में आवाज आने लगी कि अंग्रेजी में बोलिये।)

*Shri **SHITAL PRASAD BHAGAT** : Sir, I had the intention to speak in Hindi but under compulsion I have to speak in English.

DEPUTY SPEAKER : There is no point of compulsion. Kindly withdraw it otherwise you will have to walk out.

Shri **BIRCHAND PATEL** : There is a compulsion under love and affection.

श्री शीतल प्रसाद भगत—मैं वापस लेता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई की मांग का

समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूं। आशा है सरकार इसपर ध्यान देगी। सबसे पहले कहना चाहता हूं कि इस विभाग में धीरे-धीरे अधिक रुपया खर्च किया जा रहा है। वह इस प्रकार है :—

१९५१-५२	३,४०,४७,४३९ रु०।
१९५४-५५	५ करोड़ से अधिक।
१९६१-६२	२० करोड़ से अधिक।
१९६२-६३	३० करोड़ से अधिक।
१९६३-६४	२० करोड़।
१९६४-६५	२८ करोड़ से अधिक।

इतना होने पर भी किसानों की हालत अच्छी नहीं है। बिहार कृषि-प्रधान राज्य है और ८६ प्रतिशत यहां किसान हैं। हाल ही में मैं एक सप्ताह अपने क्षेत्र में था और मुख्य मंत्रीजी भी वहां थे। वहां कहीं तो पानी के बिना फसल मारी गयी और कहीं तो पानी के कारण फसल मारी गयी। बांका सबडिवीजन बिहार में सबसे गरीब है। यदि वहां सिंचाई का पूरा इन्तजाम किया जाय तो दक्षिण बिहार बहुत आगे बढ़ सकता है। कोशी योजना में ३० करोड़ रुपया खर्च होगा लेकिन यह कहा गया था कि मेरे यहां हनुमना स्कीम १९६१ में पूरी हो जायगी लेकिन अबतक यह पूरी नहीं हुई है। गत वर्ष मुंगेर जिले को पानी मिला परन्तु कैनाल के नहीं खोलने से भागलपुर जिले की हालत बहुत खराब थी। यदि वहां पानी का इंतजाम होता तो अच्छी फसल होती और लोग अपनी मालगुजारी दे देते। इसलिए सरकार से मेरा कहना है कि हनुमना स्कीम को शीघ्र किया जाय ताकि लोगों को कहने का मौका नहीं मिले कि उन्हें पानी नहीं मिला।

चानन विलासी स्कीम के लिए १४ लाख रुपया का आयोजन किया गया था लेकिन पैसा बर्बाद हो गया। मुझे खुशी है कि अब इसके लिए ४० लाख रुपया का आयोजन किया गया है लेकिन इसका काम धीरे-धीरे हो रहा है। अगर काम ठिकाने से चलेगा तो बहुत सुविधा होगी।

पंडित जी जब राजस्व मंत्री थे तो उन्होंने सिंचाई मंत्री दीप बाबू की अनुपस्थिति में जवाब दिया था कि जल्द इसकी कारंवाई की जायेगी लेकिन आज चार वर्ष हो गये उसपर पूरी कारंवाई अभीतक नहीं की गयी। गत वर्ष ८ हजार रुपया टेम्पोररी इम्बैंकमेंट के लिए खर्च किये गये थे लेकिन वह बिलकुल बर्बाद गया। मैं सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि जल्द-से-जल्द परमानेन्ट इम्बैंकमेंट को कम्प्लीट किया जाये। अब मैं चानन बिलासी स्कीम की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें १४ लाख रुपया बर्बाद हुआ। मैं सिंचाई मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ४० लाख रुपये उस स्कीम के ऊपर वेयर बनाने और वेयर के नजदीक से एक और स्कीम ले जाने के लिए दिया। वह स्कीम भदरीया, बीरमा, डुमरावां, कुलहड़िया वगैरह होते हुए जा रहा है लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो भदरीया, बीरमा वगैरह बस्ती चानन के तटबन्ध के टूट जाने से बर्बाद हो रहे हैं और अब कोशी होकर यह स्कीम ले जाया जा रहा है। यदि सुलतानपुर वगैरह गांव जिनकी सतह ऊंची है उनसे होकर यह स्कीम जाती तो अच्छा होता। वहां काम बन्द हो गया है। वहां वे लोग चाहते हैं कि इसे सिंचाई मंत्री स्वयं आकर देखें। मैं सरकार का ध्यान हनुमना गढ़ी स्कीम उर्फ बरुआ स्कीम की ओर ले जाना चाहता हूं। उस स्कीम में ४ करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये गये हैं और इससे करीब एक लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। वह स्कीम सन् १९६१ में पूरा होना था लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हुआ। उसमें दो कैनाल हैं, गत वर्ष मुंगेर जिला की आबपाशी एक कैनाल से हुई और भागलपुर जिला वाले को पानी नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि इस वर्ष दूसरे कैनाल से भागलपुर जिला वालों को पूर्ण रूप से पानी दिया जाये। क्योंकि पानी के अभाव में इस वर्ष पूरा पैदा नहीं हुआ और कोड़ा वगैरह से भी बहुत पैदावार बर्बाद हुई और इसके अलावे सरकार की ओर से मालगुजारी वसूल करने के लिए कुरकी की जा रही है। अगर इस सख्ती से मालगुजारी वसूल की जायेगी तो किसानों के पास गल्ले नहीं रहेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि दूसरे साल सरकार को किसानों को और भी मदद देने की जरूरत पड़ेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भागलपुर जिला परामर्शदातृ कमिटी में पहुंचे हुए थे, वहां भी मैंने अपने टूर की कटिंग उनको दिया था। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि मालगुजारी वसूली में सहूलियत दी जाय। इसके बाद मैं कजहिया स्कीम की ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। यह स्कीम भी करीब १६ मील की है। उसमें भी जहां-तहां वाटरफौल नहीं दिया गया है जिससे किसानों का पटवन नहीं हो रहा है। और लोगों पर वहां टैक्सेशन किया गया था जिसको हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि दो रुपया से पांच रुपये तक टैक्सेशन कर देंगे लेकिन अभीतक उसका कोई हल नहीं हुआ। कोहजीह स्कीम के बारे में अब कहना चाहता हूं, वह एक बहुत ही सुन्दर प्राकृतिक दृश्य है, तीन तरफ पहाड़ है और एक तरफ खुला हुआ है। इसके विषय में हमने बराबर असेम्बली में प्रश्न किया था। सरकार से जवाब मिला था कि जब बरुआ का पानी वहां नहीं पहुंच सकेगा तब वह स्कीम ली जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि बरुआ का पानी इसमें नहीं पहुंच सकता है इसलिए सरकार को इस स्कीम को जल्द टेकअप करना चाहिए। इससे अमरपुर थाने के सर्किल ४ और ८ के लगभग १५ हजार, २० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। अब मैं लक्ष्मीपुर डैम के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस स्कीम में करीब ५ करोड़ रुपये खर्च होंगे। उसका प्रिलिमिनरी वर्क हो चुका है। उसमें कहा गया था कि हनुमाना स्कीम के खत्म होने पर इस स्कीम का काम पूरे जोर से चलेगा। अब सरकार को उसमें पूर्ण रूप से काम लगाना चाहिए। उस स्कीम से भी करीब एक लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। ७५ हजार एकड़ जमीन के लिए वह स्टोरेज पानी का होगा। उस स्कीम के हो जाने से चानन-बिलासी स्कीम और कझिया स्कीम में बराबर पानी चलता रहेगा। इसलिए सरकार को उसके ऊपर पूर्ण रूप से

ध्यान देना चाहिए। इसके अलावे में एक और स्कीम की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। वह फुल्लो डूमर स्कीम है। उसमें सिर्फ दो सौ गज दो पहाड़ के बीच में जोड़ना है। उस स्कीम के होने से ही पन्द्रह हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होगी।

श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल—मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि उनके जिले में

और कितने डैम की स्कीमें हैं ?

श्री शीतल प्रसाद भगत—मैं कहना चाहता हूं कि दक्षिणी बिहार के लिए स्टेप-मदरली

ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं चाहता हूं कि जितना उत्तर बिहार के लिए खर्च किया जाता है उसका कम-से-कम एक-तिहाई हिस्सा दक्षिण बिहार पर खर्च किया जाय। अब मैं अंत में कहना चाहता हूं कि सिरकिया डैम के बारे में हमने असेम्बली में एक प्रश्न किया था जिसका जवाब राज्यमंत्री ने दिया था कि कारंवाई की जायेगी। वह स्कीम रक्त ग्राम, थाना अमरपुर में है। उसमें शीघ्र कारंवाई की जाय। इससे ३०० गांवों को फायदा होगा।

अंत में मैं सिंचाई मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिजली के रेट को कम किया है और उन्होंने बिजली का विस्तार किया है। मेरे गांव में भी बिजली आ गई है लेकिन इसको और बढ़ाना है। इतना ही कहकर मैं बैठ जाता हूं।

श्री परमेश्वर कुंवर—अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री का भाषण बड़े गौर से सुन रहा

था। उनके पूरे भाषण में लगा जैसे किसी अफसर ने या उनके अफसरों ने भाषण लिख कर तैयार कर दिया है और उन्होंने भाषण दिया है। मैं समझता हूं कि कोशी के बारे में उन्होंने जो बातें कहीं, इसका कार्यान्वयन जिस क्षेत्र में हो रहा है अगर उस क्षेत्र में वे गये होते तो उस योजना के बारे में इतनी बात ही कहकर समाप्त नहीं कर दिये होते। कोशी योजना की कार्यान्विती के सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोशी से जितनी जमीन की क्षति बाढ़ से होती थी, उससे आधी जमीन से ज्यादा बाढ़ से क्षतिग्रस्त होती है। इस योजना के चलते और कम से कम सरकारी आंकड़े के अनुसार एक लाख १५ हजार लोग कोशी के तटबंधों के बीच में परेशान हो रहे हैं। यह आंकड़ा मुझे सही नहीं जंचता है। मेरी समझ से आज दो लाख से अधिक लोग इस कोशी योजना के चलते परेशान हो रहे हैं। मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि जब कोशी नदी बहती थी तो करीब साढ़े चार लाख एकड़ जमीन कोशी बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त होती थी और आज जब कोशी के दोनों किनारों पर तटबंध का निर्माण किया गया है, और योजना समाप्त होने पर है, तो ऐसी हालत में चार लाख में से २.६ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो स्थाई रूप से क्षतिग्रस्त होती रहेगी जिसका कभी उद्धार नहीं होने वाला है जो सरकारी आंकड़े के मुताबिक सदा के लिये कोशी की बाढ़ में रहेगी और जो सदा के लिये बर्बाद हो गयी। इसके साथ ही साथ कोशी तटबंधों के भीतर डेढ़ लाख से अधिक इन्सानों का, जिनका सब कुछ सदा के लिये नष्ट हो गया, इसका पता सरकार को है या नहीं ? कहीं कोई निस्तार नहीं है। इस तरह कोशी योजना से इतनी एकड़ जमीन और इतनी आबादी सदा के लिये बर्बाद हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, सभी जानते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और दूसरे मंत्री भी इसको जानते हैं कि कोशी नदी जहां से होकर बहती है उसको उजाड़ देती है, बर्बाद कर देती है। पूर्णिया की आबादी इसलिये कम है कि उस इलाके में कोशी नदी बहती थी। जिस इलाके में कोशी नदी बहती है उस इलाके की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है।

उस एलाके के इन्सान की जीवन-शक्ति घटती जा रही है, पशुओं की जीवन-शक्ति घटती जा रही है जिसे कोशी नदी ने रौंदकर बर्बाद कर दिया है, और जो पूर्णिया एवं सहरसा जिले के बीच में पड़ता है।

श्री विनोदानन्द झा--मैं एक इन्फोर्मेशन चाहता हूं कि कोशी नदी के प्रकोप से वहां के लोगों की जीवन-शक्ति घटती जा रही है तो पिछले सेंसस में सहरसा जिले की आबादी कैसे बढ़ गयी?

श्री परमेश्वर कुंवर--यह हो सकता है कि पिछले सेंसस में सहरसा जिले की आबादी बढ़ी है। लेकिन मेरा कहना है कि कोशी सहरसा जिले के पूरे भूभाग को क्षतिग्रस्त नहीं करती थी, सिर्फ चार लाख एकड़ को क्षतिग्रस्त करती थी। इसके अलावे जो सहरसा जिले का एरिया है उसमें आबादी बढ़ी है जबकि कोशी के उपद्रवग्रस्त क्षेत्र का हाल बिल्कुल विपरीत है। मेरा कहना सिर्फ यही है कि कोशी नदी जिस भूभाग से होकर बहती है उसमें इन्सान की जीवनी शक्ति घटी है, पशुओं की जीवनी शक्ति घटी है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं तटबंध बनाकर कोशी नदी को कैद तो कर दिया गया है लेकिन उस तटबंध के भीतर रहनेवाले लोग तबाह हो रहे हैं, पशु तबाह हो रहे हैं। उसकी ओर माननीय सिंचाई मंत्री ने ध्यान नहीं दिया है। यह ठीक है कि बजट में उनके पुनर्वास के लिये २.१६ हजार रुपया रखा है। लेकिन कोशी नदी के तटबंधों के भीतर रहनेवाले ३०६ गांवों में हर साल करीब सैकड़ों गांव कोशी नदी से कट जाते हैं। यद्यपि उनके रहने के लिये जमीन अर्जित की गई है लेकिन वह जमीन सिर्फ उनके पुनर्वास के लिये अर्जित की गई है और वह भी एक साल के लिये बन्दोबस्त कर दी जाती है। नतीजा यह होता है कि किसान बरसात में रक्षा के लिये अपने मवेशियों को बाहर ले नहीं जा सकते। इस प्रकार उन्हें बाहर भी, और कोशी तटबंधों के भीतर भी दोनों जगहों में रहना पड़ता है; क्योंकि भीतर में आवास संभव नहीं और बाहर में उनका खेत नहीं है। इससे उनको बड़ी परेशानी होती है। सरकार को खबर है या नहीं कि ऐसा भी होता है कि जो लोग बाहर आकर बसना चाहते हैं उनकी झोपड़ी हाथी के जरिये उजाड़ दी जाती है और उन्हें मुकदमों में फंसा दिया जाता है। सहरसा जिले के घरहरा थानान्तर्गत अभाही गांव में ऐसा ही हुआ था। सरकार उन्हें बचाने का कोई उपाय नहीं करती है। इसलिये सरकार जब उन्हें जमीन बन्दोबस्त करना चाहती है और उन्हें पुनर्वासित करना चाहती है तो पूरी व्यवस्था के साथ ऐसा करे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जमीन कर्ज लेकर रिक्लेम की गई वह तटबंध बनने के कारण पुनः बर्बाद हो गयी है। उनको रिक्लेम करने का कोई उपाय नहीं हो रहा है, अतः उनका कर्ज माफ होना चाहिये। कोशी के तटबंधों के बीच रहनेवाले लोगों के बांस और लकड़ी वगैरह का कहीं पता नहीं है, कितने बगीचे थे जो बर्बाद हो गये। मैं उसी तटबंध के भीतर का रहनेवाला हूं। मेरे पास सौ सीसम के पेड़ थे लेकिन अब एक पेड़ भी नहीं बचा है, एक बांस भी नहीं बचा है। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये कि कोशी के अंदर रहनेवाले जो लोग हैं वे अपना घर बना सकें इसका इन्तजाम होना चाहिये; क्योंकि हर साल उनको घर बनाना पड़ता है। तटबंध के भीतर रहनेवाले विद्यार्थियों को स्टाइपेंड देकर पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिये। वहां कुएं का इंतजाम नहीं है। सालो भर वहां बीमारी रहती है। मवेशियों का दूध घटता जा रहा है। दूध क्रीम भी घटता जा रहा है। जब कोशी तटबंध बना तो कहा गया कि तटबंधों के बाहर स्वर्ग बनेगा। पूर्वीय तटबंध के पूरब एक लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें सालो भर पानी जमा रहता है। इसलिये बीस-पचीस हजार रुपया

खर्च करके पानी के निकास की व्यवस्था हो जाय तो एक लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है और उपज बढ़ाई जा सकती है। अगर सिंचाई मंत्री उस एलाके को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि उस इलाके का क्या हाल है। भारत सेवक समाज के चलते कोशी क्षेत्र में काफी भ्रष्टाचार, (वंर्गलिंग) बढ़ा हुआ है। जितना भ्रष्टाचार कोशी इलाके में है उतना सारे बिहार सूबे में नहीं है। भारत सेवक समाज के भ्रष्टाचार की तुलना नहीं की की जा सकती है।

श्री वैद्यनाथ मेहता—भारत सेवक समाज में तो भ्रष्टाचार निरोध विभाग भी खुला है?

श्री परमेश्वर कुंवर—हां, भारत सेवक समाज में भ्रष्टाचार निरोध विभाग भी खुला है। उपाध्यक्ष महोदय, उनमें जितने लोग हैं उनके घर और धन की जांच कराई जाय तो जिनके पास दस, पांच बीघा जमीन भी नहीं थी वह आज मालोमाल हो गये हैं, तो भ्रष्टाचार निरोध विभाग के लोग किस तरह भ्रष्टाचार रोक सकते हैं? भ्रष्टाचार भारत सेवक समाज के जरिये ही होता है। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी में भी लोग जो भारत सेवक समाज के अन्दर हैं वे अपना प्रभाव जमाये हुए हैं।

उपाध्यक्ष—शांति, शांति। माननीय सदस्य को इतनी बातें कहने का समय नहीं है। जल्द अपना भाषण समाप्त करें।

श्री परमेश्वर कुंवर—मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि भारत सेवक समाज में जितने लोग जितना काम किये हैं चाहे वह तटबंध बनाने का काम हो या और कोई काम वह आज तक काम पूरा नहीं हुआ है। मैं देखता हूं कि मेरे थाने में कम-से-कम एक लाख मजदूरों के पैसे उनके पास पड़े हुए हैं। और गलत आंकड़े देकर वे लोगों को भ्रम में डाले हुए हैं।

श्री महेश प्रसाद सिंह—माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि भारत सेवक समाज ने जो कुछ भी काम किया है उसके संबंध में अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टांस मालूम हो तो कृपया मुझे सूचित कर दें।

श्री परमेश्वर कुंवर—मैं एक दो करके गिना देता हूं....

उपाध्यक्ष—शांति, शांति। माननीय सदस्य सदन को नहीं बल्कि उसकी सूचना माननीय मंत्री को दें जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है।

श्री परमेश्वर कुंवर—मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री मेहरबानी करके एक बार कोशी इलाके में जाने की कृपा करें और देखें कि वहां की क्या हालत है। उसी तरह मनिहारी का इलाका सालों भर बाढ़ से क्षतिग्रस्त रहता है। एक बार जयप्रकाश जी वहां ग्रामदान के लिये गये तो लोगों ने कहा कि पहले हमें बाढ़ से बचायें तब ग्रामदान मांगें। ऐसी तो वहां की हालत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्रीमती राम सुकुमारी देवी—उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जिस विषय पर अभी वाद-विवाद चल रहा है वह बिहार की जनता के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान देश के प्राण हैं, वे हमारे अन्नदाता हैं, ये खेतों में मिहनत करते हैं और अन्न पैदा करके हमलोगों को जिलाते हैं। गर्मी की इठलाती धूप में किसान अपने आड़ पर बैठकर काम करते रहते हैं जबकि नौकरी पेशेवाले या दूसरे पेशेवाले धूप के भय से बाहर भी नहीं निकलते हैं, कमरे में बन्द रहते हैं गर्मी और धूप के भय से। उसी समय कृषकों की स्त्रियां गोद में बच्चे को लेकर खेतों में खाना पहुंचाती हैं और इस तरह से किसान अपने खेतों में काम करते हैं। इसी तरह से बरसात में भी किसान अपने आड़ पर बैठकर खेतों के पानी को सम्हालते रहते हैं, वे अपनी हिम्मत कभी नहीं हारते, बिजली चमकती रहती है, बादल गरजते रहते हैं लेकिन फिर भी वे अपने खेतों पर डटे रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं कह रही थी कि किसान देश के प्राण हैं। जो प्राण हैं उनकी क्या हालत है? किसानों को खेती की जमीन है, वे मिहनत भी करना चाहते हैं, अधिक अन्न उपजाने के लिये तरह-तरह के नारे भी लगाये जाते हैं। फिर भी उत्पादन बढ़ाया जाय इसके लिये किसानों को किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। कागज के पन्नों पर तो बहुत-सी बातें रहती हैं, सदन में भी तरह-तरह की योजनायें सुनने में आती हैं और दाद मांगा जाता है लेकिन दाद दें तो कैसे? किसान जब खेतों में जाते हैं तो पानी के लिये आकाश की ओर टकटकी लगाये रहते हैं और जब बारिश होती है तो उनका मन लहलहा उठता है और जब बारिश नहीं होती है तो उनका मन छटपटा जाता है और दूसरी तरफ कर-वसूली अभियान सरकार का चल रहा है। उत्तर बिहार को तो सिंचाई का शब्द सुनने के सिवाय और कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। सिंचाई के लिये मेरे तथा और जगहों में बहुत से ट्यूबवेल गाड़े गये हैं मगर कच्चा चैनल होने के कारण खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता है। चैनल कच्चा होने से टूट कर दूसरे खेतों में पानी चला जाता है और जहां जाना चाहिये वहां नहीं पहुंच पाता है। वे खेती के लिये मजदूरों को मजदूरी देते हैं फिर भी पानी नहीं पहुंच पाता है।

इसके लिये एक कमिटी बनी और उसने अपना प्रतिवेदन दिया लेकिन इसके बाद भी काम में उतनी प्रगति नहीं हुई। ट्यूबवेल से किसानों को कुछ लाभ नहीं हुआ है। जब कभी सिंचाई की बात आती है तब मैं यही कहूंगी कि जो ट्यूबवेलस् हैं कम-से-कम चैनेल बना दीजिए जिसमें किसानों को उत्पादन बढ़ाने में फायदा हो। उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है इसलिये मैं संक्षेप में कहना चाहती हूं कि उत्तर बिहार में नहरों की कमी है उसके लिये आप अवश्य कुछ कीजिए। उत्तर बिहार में हिमालय से निकल कर कोशी, बागमती और गंडक आदि नदियां निकलती हैं उन्हें बांधकर किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं लेकिन जो सिंचाई योजनाएं सरकार बनाती है उससे कहां तक किसानों को फायदा होता है यह सबको मालूम है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हयाघाट में एक बांध बांधा गया और उसको कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया गया जिसका नतीजा हुआ कि किसानों के खेतों में पानी समा गया और उनकी उपज बरबाद हो गयी। माननीय मंत्री और राज्य मंत्री हमारे क्षेत्र में गये थे। किसानों को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। किसान बिजली घर में नहीं चाहते हैं वे चाहते हैं कि उनको उत्पादन बढ़ाने में सरकार मदद करे लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सिंचाई मंत्री अभी तक कुछ नहीं कर सके हैं। इसकी लिये तहकीकात होनी चाहिये लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि उत्तर बिहार के लिये समस्यायें हैं और वे गंभीर समस्यायें हैं। वहां का मनी क्रौप सूगरकेन सेस और मिरचाई है। बाढ़ की वजह से

सूगरकेन की उपज भारी नहीं जाती है लेकिन वह भी आज उपेक्षित है। सरकार की यह उपेक्षित भावना शोभा नहीं देती है। सिंचाई मंत्री उसी क्षेत्र से आते हैं जहां से मैं आती हूं। वे थोड़े ही दूर पर हैं। जब वे जनता के बीच में आते हैं तो जनता लोग उनको अपने बीच पाकर बहुत खुश होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन किसानों को क्या मिलेगा ? मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगी कि उन्हें बाढ़ से बचाने के लिये आश्वासन देना चाहिये और फ्लड कंट्रोल के अलावे यह भी करना जरूरी है कि जगह-जगह पर जहां आवश्यकता हो स्लुईस गेट बनाया जाय। स्लुईस-गेट होने से बाढ़ के समय में बाढ़ नियंत्रण का काम होगा और उसके बाद सिंचाई का काम भी हो सकेगा। मेरा यह अनुरोध है कि किसानों के ऊपर बहुत उपकार होगा अगर जल्द-से-जल्द बरसात शुरू होने के पहले काम पूरा कर दिया जाय। मैंने यह बराबर अनुरोध किया है या तो बांध बांधने की नीति सरकार उठा ले या बांध बांधकर या आवश्यकता हो तो बांध का एक्सटेन्शन करके किसानों को सिंचाई की सुविधा दे।

दूसरी बात यह है कि बहुत से वर्क सरकारों को बेरोजगार कर दिया गया है। इतने बड़े विभाग में जहां बहुत सारे ऑफिसर्स और ओवरसियर्स आदि के लिये काम है और सरकार उन पर काफी पैसे खर्च कर रही है वहां वर्क सरकार के लिये काम न हो और उन्हें बेरोजगार कर दिया जाय मेरी समझ में इसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिये सरकार को उ।की तरफ ध्यान देना चाहिये जिसमें उनलोगों को काम मिले। इससे अनएम्प-लायमेंट नहीं बढ़ेगा और योजनाओं के काम में भी काफी सुविधा होगी। पश्चिमी कोशी और गंडक योजना के विस्तार के संबंध में कहा गया है कि उसका कमान्ड एरिया बढ़ाया जायगा। जहांतक हमारे वारिसनगर की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, कोशी योजना जयमलपुर होकर और गंडक योजना ताजपुर होकर निकल जायगी और उससे हमारे क्षेत्रको कोई लाभ नहीं है। इसलिये हमारे क्षेत्र में भी किसानों का उत्पादन बढ़े इसके लिये सरकार को ध्यान देना चाहिये।

*श्री श्रीकृष्ण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सूरज प्रसाद के कटौतीके प्रस्ताव का समर्थन

करते हुए कुछ बातें संक्षेप में निवेदन करूंगा। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने अपनी बातें सदन के सामने रखी हैं उससे सदन को यह पूरी तरह से अवगत हो चुका है कि बिहार की स्थिति कृषि में, पैदावार बढ़ने में और प्रदेशों की तुलना में अच्छी नहीं है बल्कि यहां की पैदावार घट रही है और सिंचाई के कमान्ड एरिया में कोई प्रगति नहीं हो रही है जो कि उल्लेखनीय हो।

दूसरे स्टेट की औसतन आमदनी और प्रति व्यक्ति आमदनी का कुछ आंकड़ा मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

आसाम—औसतन आमदनी १६५ रु० और प्रति व्यक्ति आमदनी २०८ रु०।

उड़ीसा—औसतन आमदनी ६३ रु० और प्रति व्यक्ति आमदनी ८८ रु०।

यू० पी०—औसतन आमदनी १२४ रु० और प्रति व्यक्ति आमदनी १७६ रु०।

बंगाल—औसतन आमदनी २१५ रु० प्रति और व्यक्ति आमदनी ११३ रु०।

बिहार—औसतन आमदनी १०७ रु० प्रति और व्यक्ति आमदनी ५७ रु०।

उपरोक्त आंकड़ों को देखने से पता चलेगा कि जो तसवीर बिहार की खींची गयी है वह भ्रमात्मक है। अभी जब माननीय मंत्री सदन में बोलते हैं तो सिर्फ उत्तर बिहार का हवाला दिया जाता है और उसी का नारा लगता है और मेरे जानते यह सिर्फ अपनी लोकप्रियता

बढ़ाने के लिये ही नारा लगता है। उत्तर बिहार की वास्तविक उन्नति हुई या नहीं इसे माननीय मंत्री और वहां के माननीय सदस्य ही जानते होंगे लेकिन दक्षिण बिहार के बारे में तो यह भ्रमात्मक ही मालूम होता है। बिहार की औसतन आमदनी और व्यक्तिगत आमदनी सबसे कम है। अभी भागलपुर में बडुआ स्कीम चल रही है और अभी हमारे माननीय सदस्य, श्री शीतल प्रसाद भगत वहां की हनुमानगढ़ी स्कीम का भी जिक्र किया है। वहां पर क्या हो रहा है और किस तरह से काम हो रहा है ? वहां इंजीनियर और टेकनिकल हेंड्स बैठे हुए हैं और या तो ताश या सतरंज खेलते हैं या जीप लेकर घूमते रहते हैं। नकी सेवा का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। पहले इस विभाग के मंत्री दीप बाबू थे और आज तो महेश बाबू इंद्र भगवान बनकर बैठे हुए हैं। इनके जमाने में भी आलस और अकर्मण्यता का वही बोलबाला है जो पहले था। कृषि और सिंचाई विभाग एक ही मंत्री के जिम्मे रहना चाहिये लेकिन अभी तो आधा कृषि एक मंत्री के जिम्मे है तो आधा किसी दूसरे मंत्री के हाथ में है। इसका तो यही नतीजा होता है कि :

"चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय,
दो चक्की के बीच में साबित बचा न कोय।"

और बिहार के लोग भी दो हाथों में एक ही विभाग का काम रहने से पीसे जा रहे हैं। मोकामा और बड़हिया योजना की बात होती है। लेकिन हमारे मुंगेर जिले की भी एक योजना है जिसके लिये केन्द्रीय सरकार से भी रुपया मिला हुआ है लेकिन फिर भी उसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। उत्तर बिहार के साथ ही साथ छोटानागपुर का नाम भी घसीटा जाता है। छोटानागपुर के एक दो आदिवासी को कैबिनेट में ले लेने से लाखों लाख आदिवासी लोगों की समस्या क्या हल हो गयी है और क्या वहां की पथरीली जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ गयी है ? हमारे जिले में सिमलतल्ला से आगे एक बड़ा ही रमणीक स्थान है जहां पर बंकिम बाबू रहते थे और वहीं उन्होंने अपनी किताबें भी लिखीं लेकिन आज वहां पर भी भुखमरी की समस्या है और वहां के लोग, औरत और बच्चे खोखा फल को खा-खाकर अपना जीवन बिता रहे हैं। आज वहां पर सिंचाई का साधन नहीं रहने से अकाल का दृश्य उत्पन्न हो गया है। अगर अजय नदी में एक बांध बांध दिया जाय तो उसके नीचे के हिस्से की सिंचाई हो सकती है और जमीन की पैदावार बढ़ सकती है। लेकिन सरकार का इधर ध्यान न जाकर बार-बार उत्तर बिहार की दुहाई दी जाती है और ऐसा होने से मालूम पड़ता है सिंचाई विभाग शीर्षासन कर रहा है। सारी चीजों को चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाता है।

तो जो चुनाव होता है उसमें पक्षपात होता है। जिसका चुनाव भी होता है और उसके लिये सामान भी भेज दिया जाता है पर काम करने में बहुत समय लगाया जाता है। अगर सामग्री रही तो टेकनिकल हेन्ड नहीं रहते हैं जिसके बिना काम रुका रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे यहां जो काम होता है उलटा ही होता है। पहले मकान बन कर तैयार हो जाता है और उसके बाद सामान भेजा जाता है लेकिन सामान भेजने के बाद टेकनिकल हेन्ड नहीं रहता है जिसके द्वारा काम शुरू किया जा सके और अगर टेकनिकल हेन्ड रहता है तो सामान नहीं रहता है। तो मेरा कहना है कि काम करने के तरीके ऐसे हों जिससे साधन का सही इस्तेमाल हो सके चाहे वह उत्तर बिहार का काम हो या दक्षिण बिहार का काम हो। इसके साथ-साथ इनका इरादा भी मजबूत होना चाहिये। जो स्कीम बनती है वह इनके आफिसर द्वारा ही बनती है और आफिसर स्कीम बनाकर इनके सामने रख देते हैं लेकिन जिस ढंग से काम होना चाहिये उस ढंग से काम नहीं होता है। आप कहते हैं कि मेरे साथ आप ताली बजाइये। लेकिन आपके साथ हम कैसे ताली

वजावें जबकि आपके आफिसर लोग किसी काम को करने में बंगलिंग करते हैं। ये गलत काम भी करते हैं और उसके बाद आप उनका पीठ भी ठोकते हैं। अगर आपका अच्छा काम होगा तो उसका नतीजा बहुत अच्छा अपने से निकलेगा। आज महंगी बढ़ती जा रही है। आज चावल ३६ रु० मन बिक रहा है लेकिन आपका ध्यान इसकी तरफ नहीं जा रहा है। हमारे क्षेत्र में जो मुरलीगंज इलाका है वहां के जितने कलवर्ट थे उसमें ठीक अनुपात में सिमेंट नहीं देने की वजह से सभी कलवर्ट टूट गए। हमारे ही क्षेत्र में एक डुमरी इलाका है जहां चैनल नहीं दिए जाने के कारण वहां पानी जमा हो गया और वहां बर्बादी रहा है। यह क्यों हुआ? मेरा कहना है कि यह हुआ सिंचाई मंत्री के पक्षपात के कारण। वहां के एक आदमी हैं जिनका सिंचाई मंत्री पर दबाव है और इस दबाव के कारण ही वहां चैनल नहीं हो सका जिसका नतीजा यह है कि वह गांव बरबाद हो रहा है। अभी आपके हाथ में पावर है और आप जैसे अपने इंजीनियर को कहेंगे, यानी अगर कहेंगे कि उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर कर दो तो वह कर देगा। आपके हाथ में पावर है, आप सिंचाई मंत्री बने हुए हैं, आप इंद्र भगवान हैं इसलिये जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। आपके कारण कुछ लोग मनमाना कर रहे हैं। आज बिना टेन्डर कौल किए हुए ही लोगों को ठीका दे दिया जाता है और उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो आपके चुने हुए लोग हैं। मेरे पास इसका प्रमाण है पर मैं अभी उसको आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं। आज बिना टेन्डर कौल किए ठीका दे दिया जाता है और इस कारण से आज लूट हो रहा है। आप पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब करते हैं, जैसी हवा चाहते हैं, वहां देते हैं और इसके बीच में बेचारा इंजीनियर पिस जाता है। हम चाहते हैं कि सिंचाई मंत्री अपने इरादे को बदलें। मुख्य मंत्री ने कहा था कि वे बिहार को हिन्दुस्तान के नक्शे पर लाना चाहते हैं तो इसके लिये आपका इरादा पक्का होना चाहिये। हमारे सबडिवीजन में कोयल नदी है जिसको अगर बांध दिया जाय तो १६ हजार एकड़ जमीन पट सकती है। यह नदी पेरेनियल नहीं है, यह सीजनल है। तो उसमें चैनल बना देना चाहिये। एक कसवा गांव है जहां पहले फर्दआबपाशी के जरिये सिंचाई होती थी और वहां पइन भी था लेकिन पइन के टूट जाने की वजह से वह गांव बरबाद हो गया। इसलिये इसको भी बनवा देना चाहिये। जब श्रीबाबू मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हमारे इलाके के लिये एक विधेश्वर स्कीम बनवाया था जिसके जरिये एक डैम बनता। उसका सर्वेक्षण भी कराया गया था और कहा गया था कि इस डैम के बन जाने से वहां का कायापलट हो जायेगा लेकिन आजतक वह नहीं बना।

उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री महेश प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, श्री श्रीकृष्ण सिंह जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि सिंचाई मंत्री पर एक आदमी का दबाव है। मैं उनको बीच में रोकना नहीं चाहता था। मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर किसी आदमी का दबाव नहीं है और यह गलत बात है। आप लिखकर दें कि किसके दबाव में वह चैनल नहीं बनाया जा सका।

श्री हेमलाल प्रगनैत—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सिंचाई मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में दो थाने हैं। इन थानों में कई एक नाले हैं जो स्थानीय पारसनाथ पहाड़ से निकलते हैं। अगर उनको बांध दिया जाय तो दोनों थाने की जमीन पट सकती है। आज कई वर्षों से जो जमीन परती पड़ी हुई है उसमें से अधिकांश इन नालों के बांध दिये जाने से पट जायेगी।

पहाड़ों से जितने नाले निकलते हैं, उन नालों में हमेशे ही पानी रहता है जिससे सिंचाई हो सकती है। डुमरी थाने के हटवार और पुतरीगढ़ नालों को बांध देने से हजारों एकड़ जमीन पट सकती है। इस थाने में कई एक नाले और हैं उन सबको बांध देने से बहुत-सी जमीन पट सकती है। पीरटाड़ थाना में भी कई एक नाले हैं, उदाहरणतः नाला केंदुआडीह जो कुरको मौजा में होकर बहता है, उन को भी अगर बांध दिया जाय तो ५-७ हजार एकड़ जमीन उनसे पट सकती है। कुरको में आज कई एक वर्षों से पानी नहीं होने की वजह से वहां की जमीन परती पड़ी हुई है। अगर नाला बांधकर रानी बांध में गिरा दिया जाय तो वहां की जमीन पट सकती है। कुरको में एक रानी बांध है जो मीडियम इरिगेशन स्कीम के अन्तर्गत २८ हजार रुपये खर्च कर बनाया गया, पर उससे कोई लाभ नहीं हो सका। जब तक उक्त केन्दुआ नाला को बांध कर तालाब में नहीं गिराया जायेगा तबतक कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा करने से वहां की जमीन पट सकती है। अब मैं लघु सिंचाई के संबंध में कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष—आप लघु सिंचाई के संबंध में अभी न कहें।

श्री हेमलाल प्रगनैत—तो मेरा कहना है डुमरी थाना में एक मटियो नाला है जो मीडियम इरिगेशन के अन्दर है और जो कई वर्षों से टूटा पड़ा है। उसकी मरम्मती नहीं की गयी है। उस मटियो नाला को मरम्मत कर दिया जाय तो लोगों को फायदा हो सकता है। इसके अलावा हमारे मौजा में एक शिवसागर डैम बना हुआ है। उसके चैनेल को टूटे हुए आज कई एक वर्ष हो गये जिसे आजतक नहीं बांधा गया है। इसके बारे में जिला एडवाइजरी कमिटी और ब्लौक डेवलपमेंट कमिटी में कितनी बार प्रस्ताव भी लाया गया लेकिन वह आज तक नहीं बन सका। इससे एक एकड़ जमीन परती रह जाती है और पानी से वह जाने के कारण पैदावार नहीं हो पाती।

इसके अलावा रांची जिला में सिली थाना में एक डुमर करही नाला है। अगर इसको मेजर स्कीम में ले लिया जाये तो इससे २ हजार एकड़ जमीन पट सकती है। हमारे क्षेत्र में बहुत-सी पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों से बहुत-से नाले निकले हुए हैं। इन नालों को अगर बांध दिया जाये तो दोनों थानों में सिंचाई हो सकती है, पूरा धान भी हो सकता है और रबी की फसल भी काफी हो सकती है।

*श्री प्रेमचन्द मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो हमारे सिंचाई मंत्री द्वारा मांग उपस्थित की गई है उसका मैं समर्थन करता हूं। आपने कोशी की चर्चा की है जहां तक वहां के लाखों-लाख लोगों के जीवन और मरन का प्रश्न था इसके लिये जो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सराहनीय कार्य हुए हैं तटबंध के संबंध में, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद दे सकता हूं। लेकिन इसके आगे की जो प्रक्रिया है और जिस नीति से इसका संचालन किया गया है वह कार्यक्रम ऐसे चपेटे में पड़ा हुआ है कि आज भी तटबंध के बीच लोग जिन्दगी और मौत के हिंडोले में डोल रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप कम-से-कम एक बार अपनी आंखों से देख आयें कि वहां का क्या नजारा है और हर साल कमला बलान और कोशी के बीच जो करेह, क्षांक, सुगवैमरकंन, सुपैन और गेहुवां नदी में जो भयंकर बाढ़ आने की समस्या है उससे कितने लोग तबाह हो रहे हैं। इस तरह इससे तो समस्या का समाधान नहीं हुआ। न रोग का समाधान हुआ न रोगी का। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आपका जो टारजेट है उसके लिये बहुत ढिलाई से काम चल रहा है। झंझारपुर

से बीसभगवानपुर तक बांध अबतक बन जाना चाहिये था लेकिन यह नहीं बन पाया है। पिछले साल भी मैंने आग्रह किया था कि सरकार इसमें ढिलाई नहीं करे। आप अगर हमसे इसके लिये २८ करोड़ चाहते हैं तो लीजिए, ५६ करोड़ भी चाहते हैं तो लीजिए लेकिन पैसे को पानी की तरह नहीं बहाइये, नहीं तो न सरकार का पानी रहेगा न कुछ होगा, सभी लोग पानी पानी हो जायेंगे यह जनता की आवाज है, उनके दिल की पुकार है जो आपके सामने रख रहा हूं। आप वहां जाते नहीं हैं, आपके अफसर जाते नहीं हैं, वे कई नदियों के बीच में घिरे हुए हैं। पिछले साल कोशी का बांध टूट गया तो क्या हाल हुआ यह सभी जानते हैं। कठिनाई यह है कि आप कागज पर योजना बनाते हैं, जमीन पर नहीं बनाते। यह नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोशी योजना के बारे में पढ़कर सुना देना चाहता हूं जो इस प्रकार है:

"आपको यह जानकर हर्ष होगा कि बड़ी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को कार्यरूप देने की दिशा में काफी प्रगति हुई है। कोशी योजना की दो मुख्य इकाइयां, तटबंध और बराज पूरी की जा चुकी हैं। तीसरी इकाई, अर्थात् पूर्वी कोशी नहर का काम पूरी तेजी से चल रहा है और संभव है कि इससे कुछ स्थानों में इसी वर्ष सिंचाई की जा सके। पश्चिमी कोशी नहर का काम तब हाथ में लिया जायेगा जब इसके लिये अपेक्षित जमीन हमें नेपाल सरकार से मिल जायेगी। यथासमय निधि का उपबंध भी कर दिया जायेगा जब काम शुरू होने को होगा।"

यह चीज है, उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री प्रभावशाली, काम करने वाले और एक लगनशील व्यक्ति हैं। जनता को उनमें पुरजोर विश्वास है और अगर वे चाहेंगे तो यह काम पूरा हो जायेगा।

उपाध्यक्ष—अब आप बैठ जायं।

श्री प्रेमचन्द मिश्र—सिर्फ दो मिनट में मैं समाप्त कर देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के भाषण से उस क्षेत्र के लोगों में संतोष नहीं है। मुख्य मंत्री महोदय ने भी पश्चिमी नहर के एक्जीक्युशन के बारे में कोई खास चर्चा नहीं की है। मैं कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय को स्वयं नेपाल सरकार से जाकर के इसका कार्यान्वयन कैसे हो इसके बारे में बातचीत करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष—अब आप बैठ जायं।

श्री प्रेमचन्द मिश्र—एक मिनट और मुझे दिया, जाय उपाध्यक्ष महोदय। मैं यह कहना

चाहता हूं कि पश्चिम कोशी तटबन्ध और कमला बलान तटबंध के बीच जो नदियां, जैसे धाको, भरकैन, सगरेव, तुर्कन आदि नदियां गेहुआं नदी में आकर मिलती हैं और इन्हीं नदियों की बाढ़ से हजारों एकड़ जमीन सालो भर पानी के तले रहती है और खेत की सारी फसल मारी जाती है। इस गेहुआं नदी का चैनल केवल आधा फर्लांग मिट्टी से भरा हुआ है। यदि उसे नहर के रूप में परिणत कर दिया जाय तो इन नदियों से जो बाढ़ आती है उसका नियंत्रण होगा। एक बात और मैं यह कहकर बैठ जाना चाहता हूं कि अभी उस क्षेत्र

में वाटरवेज डिपार्टमेंट का सर्वे चल रहा है। उस विभाग को उस नदी का सर्वेक्षण करना चाहिये। वह दूसरा काम कर रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है।

अन्त में मैं सरकार से कहूंगा कि जो चीज बजट में शामिल नहीं है उसे शामिल करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि इसकी ओर सरकार ध्यान दे।

*श्री सहदेव महतो—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े समय में जिन बातों की चर्चा माननीय

सदस्यों ने की है उन सारी बातों का सरकार की तरफ से समुचित उत्तर दिया नहीं जा सकता है। फिर भी जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव के द्वारा सरकार को लाभान्वित किया उनके प्रति सरकार आभार प्रगट करती है। थोड़े समय में उन बातों का उत्तर देने की मैं कोशिश करता हूं और जिन बातों की चर्चा न की जा सके उनके बारे में माननीय सदस्य यह न समझें कि उन बातों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है, थोड़ा समय जो प्राप्त हुआ है वही इस लाचारी की वजह है।

यह कहना ठीक है कि राज्य को समृद्धिशाली बनाने के लिये सिंचाई की व्यवस्था प्रमुख है खासकर ऐसे राज्य में जहां लेखा-जोखा लेनेवाले का कहना है कि ८५ प्रतिशत लाग खेती पर निर्भर करते हैं। इस राज्य के मुख्य मंत्री ने प्रण लिया है कि और इस राज्य को जो सारे हिन्दुस्तान में पिछड़ा हुआ राज्य है उसको हिन्दुस्तान के मैप में लाना चाहते हैं। यह ठीक है कि सिंचाई की समुचित व्यवस्था के बाद भी इस राज्य को समृद्धिशाली बनाने में कठिनाई है। लेखा-जोखा लेनेवाले यह भी कहते हैं कि सारे मुल्क की जो पैदावार जमीन है बिहार में सबसे ऐभरेज कम है। इसका कारण यह है कि सिंचाई का समुचित प्रबंध नहीं है और किसानों में भावना की कमी है क्योंकि उन्हें बाढ़ से बरबादी का भय है, सुखार से बरबादी का भय है और इस कारण वे अच्छे बीज नहीं बोते और आधुनिक तरीका जो खेती का है उसको नहीं अपनाते और न जो आधुनिक खेती के औजार हैं उनको व्यवहार में लाते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए यह मास्टर प्लान बनाया गया है। हमारे माननीय मंत्री ने मांग पेश करते हुए सभा के सामने रखा कि किस तरह से आबाद करने वाले जमीन को हम चाहते हैं कि एश्योर्ड इरीगेशन की व्यवस्था की जाय। इसके तरफ सरकार काफी सचेष्ट है।

अब मैं एक बात का जिक्र कर देना चाहता हूँ। माननीय सदस्य श्री सूरज प्रसाद ने चर्चा की है चैनेल के बारे में।

माननीय सदस्य इस तरह का जिक्र करते हैं तो ठीक है लेकिन उनको ऐसा जिक्र करना चाहिये था जिससे लोगों का उत्साह बढ़ता मगर ऐसा न करके माननीय सदस्य ने कहा कि बाप का जन्म नहीं हुआ और बेटा का जन्म हो गया। उन्होंने कहा कि चैनेल बन गया लेकिन बराज नहीं बना। इसी सदन में चन्द्रशेखर बाबू ने इस तरह का जिक्र किया था बिजली के मामले में कि प्लान बनाकर जेनरेट करते हैं उसके पहले ट्रांसमीशन की चर्चा होनी चाहिये थी। हम चैनेल बनाकर बराज बना रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ठीक उसी तरह की बात होगी जैसा माननीय सदस्य ने किया था चैनेल के बारे में।

चैनेल बनाने की व्यवस्था हुई है। गांव-गांव में ग्राम पंचायत के द्वारा चैनेल बनाया जाय और उसका खर्च गांव के रहनेवाले हैं वे दें। उसमें गड़बड़ी होने पर गांववालों की जिम्मेवारी रहेगी। अगर वे लोग नहीं बना पायेंगे तो सरकार द्वारा बनाया जायगा। इस संबंध में एक बिल विधान-सभा में आयगा जिसके द्वारा यह व्यवस्था होगी।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह--आपने मास्टर प्लान की चर्चा की। मैं जानना चाहता हूं कि हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, मानभूम, संथालपरगना और पलामू में कितना रुपया दिया है?

श्री सहदेव महतो--यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। गंडक बराज के बारे में, सोन बराज के बारे में, बरूआ डैम के बारे में चर्चा की। क्या सारे के सारे उत्तर बिहार में पड़ते हैं? जहां पर जो नदी है, जहां पहाड़ी इलाका है छोटी-छोटी पहाड़ियों के बीच में पानी जमा करके सिंचाई का प्रबंध किस तरह हो, उत्तर बिहार में गंडक, कोशी योजना की चर्चा की, दक्षिण बिहार में सोन बराज की चर्चा की, बरूआ डैम की चर्चा की। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का भेदभाव रखकर राज्य सरकार समस्याओं के समाधान का प्रयास नहीं करती, राज्य सरकार तो सोचती है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा वह कर सकती है जनता को समृद्धशाली बनाने के लिये।

हमारे डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन ने माइनोरिटी कम्युनिटी के ग्रेवयार्ड की चर्चा की और दूसरी बात उन्होंने रखी कि चीफ इंजीनियर को, गंडक का सारा काम जब उत्तर बिहार में होता है तो उनका हेडक्वार्टर वहीं होना चाहिये वे पटने में हेडक्वार्टर रख कर कैसे वहां के काम को देख सकते हैं। मैं जानता हूं कि वे उस इलाके से आते हैं जहां गंडक की शुरूआत है मगर साथ ही साथ दक्षिण बिहार के रहनेवाले श्री रामानन्द तिवारी भी कह सकते हैं कि सोन बराज हमारे यहां चल रहा है तो उनका हेडक्वार्टर हमारे यहां हो तो यह कैसे होगा? हमें जहां तक याद है एक माननीय सदस्य ने इस संबंध में एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन किया है जिसका जवाब आ गया है। समय पर उसका जवाब मिल जायगा।

ग्रेवयार्ड के बारे में भी रिपोर्ट आयी है, उस संबंध में कलक्टर के द्वारा छानबीन की जा रही है।

श्री रउफुल आजम--मैं जानना चाहता हूं कि यह सर्वे आपरेशन १९६० में हुआ था?

श्री सहदेव महतो--जी हां, लेकिन जिस ग्रेभयार्ड के बारे में आप पूछ रहे हैं और जिसके लिये आपने अल्पसूचित प्रश्न भी पूछा है उसका सबूत नहीं मिला है किन्तु अभी आपके प्रश्न के लिये जांच-पड़ताल जारी है।

वेस्टर्न कोशी कैनाल की चर्चा हुई है जिसके बारे में मंत्रीजी ने भी आपको बताया है। इसके संबंध में हमें नेपाल से भी पूछताछ करनी पड़ी है, बातचीत में कुछ देरी हुई है। हमारी सारी कोशिश के बाद भी देरी हुई है जो हमारे हाथ की बात नहीं है। कारण कि इसका संबंध नेपाल राज से भी होता है।

अब मैं इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने इस बात की भी चर्चा की है आपके मशिनरी के लोग अपना समय ताश खेलने में बिता देते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूं और सोन बराज का उदाहरण देना चाहता हूं जिसे श्री रामानन्द तिवारी जी अच्छी तरह से जानते होंगे कि वहां हमारे कर्मचारी किस मुस्तैदी से दिन-रात काम करते हैं। उनकी मुस्तैदी के कारण ही यह एक वर्ष पहले काम पूरा होने जा रहा है। आप देखे होंगे कि हमारा बरूआ डैम सारे हिन्दुस्तान में एक नमूना है और अपने ढंग का बनाया गया है। केन्द्रीय मंत्री डा० राव भी इसे देख चुके हैं और उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की है। कोशी को सदन के माननीय सदस्य को देखने

का मौका मिला होगा, किस तरह से जंगली क्षेत्र में हमारे नौजवान इंजीनियर जहाँ सांप आदि का डर बना रहता है, अपने काम में लगे रहते हैं और छानबीन करते रहते हैं। अब मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

श्री के० बी० सहाय—उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि ये सोन बराज जो बन रहा है वह देखने के लायक है, उसे इन्हें देखना चाहिये। मैं चाहता हूं कि हाउस के जितने सदस्य हैं अगर कहें तो मैं उन्हें वहां ले जाने और ले आने का सारा प्रबंध कर दूं और माननीय सदस्य अपनी सुविधा के मुताबिक प्रोग्राम मुझे दे दें। सोन बराज का पुल पी० डब्लू० डी० की ओर से बन रहा है और बराज सिंचाई विभाग की ओर से। अभी यह अन्डर-कंस्ट्रक्शन में है और अभी ही देखने के लायक है। माननीय सदस्य जो सुविधा चाहेंगे हम उसका प्रबंध कर देंगे।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है :

That the provision of Rs. 1,72,23,500 for "Irrigation, etc. (Commercial)" be omitted.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"बहुधंधी नदी योजना सहित सिंचाई" के संबंध में ३१ मार्च १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये २८,०४,८३,५८४१० से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा सोमवार, दिनांक ६ अप्रील १९६४ के ११ बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की गई।

गोविन्द मोहन मिश्र,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

पटना :
दिनांक ३ अप्रील १९६४।